

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून

दिनांक ०२ दिसम्बर, 201४

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी हवाई पट्टी के उच्चीकरण, विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यवृत्त संख्या 1660/38-रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य० संस्था के माध्यम से प्राप्त पुनरीक्षित आंगणन धनराशि 6019.34 लाख प्राप्त किया गया जिसे व्यय वित्त समिति(EFC) द्वारा रू० 5678.21 लाख औचित्यपूर्ण पाया है, से वित्त वर्ष 2012-13 में अवमुक्त धनराशि रू० 4819.63 लाख को समायोजित करते हुए शेष धनराशि 858.58 लाख को निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेख कराना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में परियोजना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कार्यदायी संस्था के माध्यम से धनराशि रू० 6491.98 लाख के आगणन प्रस्तुत किये गये, जिसे वित्त विभाग की टी०ए०सी० द्वारा रू० 4819.63 लाख औचित्यपूर्ण पाया गया, जिसके क्रम में शा०स० 257 दि० 6-12-2012 के द्वारा धनराशि रू० 300.00 लाख, शा०स० 03 दि० 9-1-2014 के द्वारा धनराशि रू० 1300.00 लाख एवं शा०स० 64 दि० 26-3-2014 के द्वारा धनराशि रू० 900.00 लाख तथा शा०स० 40 दि० 27-3-2015 के द्वारा धनराशि रू० 2319.63 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू० 4819.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपरोक्त शासनादेशों के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है, इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि रू० 6019.34 से पूर्व में निर्गत धनराशि रू० 4819.63 लाख (5678.21-4819.63=858.58) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू० 858.58 लाख (रू० आठ करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठावन हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1)- योजना निर्माण में NBC/UCADA/DGCA से संबंधित समस्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2)- कार्य कराने से पूर्व भूवैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
- (3)- कार्य निर्धारण अवधि में आवश्यक पूर्ण कर लिया जाय। इस आंगणन के पश्चात कोई भी आंगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- (4)- निर्माण सामग्री यथा Pavement material, Bricks, Cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
- (5)- आंगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी०पी०आर० की दरें ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मर्दे एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय मर्दों के आगणन में समायोजन करेंगे।

- (6)– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (7)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (8)– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (9)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (10)– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (11)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (12)– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (13)– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था/उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (14)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 31.3.2012 तक अवश्य कर लिया जाय। निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि दिनांक 31-03-2017 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम का समायोजन दिनांक 31-3-2012 तक अवश्य कर दिया जायेगा।
- (15)– धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16)– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।
- (17)– कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02-विमानपत्तन 800-अन्य व्यय आयोजनागत 99-नैनीसैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण 24-वृहद निर्माण मद के नाम में क्रमशः डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1034/XXVII (2)/2016, दिनांक 11 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।


संख्या-36 (1)/2012/22/ ix/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।

2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. राज्य योजना आयोग को इस आशय से कि वे उक्त परियोजना की गुणवत्ता परीक्षण के कार्य expert/specialised संस्था यथा आई0आई0टी0/सी0बी0आर0आई0 रुड़की अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्था से अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट से इस विभाग को भी अवगत करायेगे।
4. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2
- ✓ 8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,


(चिरंजी लाल)
अनुसचिव।